अनुसूचित भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को नवम्बर 1987 में जारी किए गए अपने पहले के निर्देशों को अगस्त 1993 में दोहराते हुए कहा है कि बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित सभी संबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भाग के रूप में लैक्चर के उपयुक्त सत्र, प्राथमिकता क्षेत्र का वित्तपोषण और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आदि शामिल करने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय बहुल वाले पता लगाए गए 41 जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के ऋणकर्ता खातों की संख्या मार्च, 1990 में 12.25 लाख थी। यह संख्या मार्च 1993 में बढ़कर 13.60 लाख हो गई। इन अल्पसंख्यक समुदाय बहुल वाले पता लगाए गए 41 जिलों में इसी अवधि के दौरान बकाया राशियां 721 करोड़ रुपए बढ़कर 952 करोड़ रुपए हो गई। देश के भी जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों को प्राथमिकता क्षेत्र का ऋण भी मार्च 1990 में 4,332 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 1993 में 5,675 करोड़ रुपए हो गया। अल्पसंख्यक समुदाय के ऋण कर्ता खातों की संख्या भी मार्च 1990 में 53 लाख से बढ़कर मार्च 1993 में 57 लाख हो गई।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जन प्रतिनिधियों के पदों की रिक्तियां

2609. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्धन में निर्वाचित/नाम-निर्देशित किए जाने वाले जन-प्रतिनिधियों के कई पद काफी समय से रिक्त हैं जिससे जन-प्रतिनिधित्व पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में, प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक-बोर्ड में नौ गैर-सरकारी निदेशक नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है। इस समय 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों के 85 पद खाली पड़े हैं। सरकार ने इन खाली पदों को भरने के लिए पहले ही आवश्यक कार्रवाई आरम्भ कर दी है।

POOR PERFORMANCE OF PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS

2610. PROF. SAURIN BHATTACHARYA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) on what basis did the Finance Minister exonerate Managements of Public Undertakings from the responsibility for poor functioning of P.S.Us;

(b) when he blames political interferences besides lack of work culture, what part of the management is the product of political interference;

(c) how the Management can be exonerated from the responsibility for the ills of P.S.Us; and

(d) whether lack of work culture concerns workers and it is not anti-workers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : (a) to (d) The unsatisfactory performance of a number of public sector undertakings (PSUs) is due to a variety of factors such as huge cost and time over-runs in project implementation, adverse locational and investment decisions in some sectors and implicit low return for reasons of high risk involved for supply of basic infrastructural goods and services. Government has since undertaken a number of reforms in the public sector. These reforms include, inter-alia, phasing out of Budgetary support in the form of non-plan loans to loss-making enterprises; disinvestment upto 49 per cent in select profit making enterprises for mobilising non-inflationary resources for the Budget, as also for broad basing ownership and creating a greater commercial ori-